सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 684
05/09/2019

महामहिम राज्यपाल को 'पोषण माह' के आयोजन से संबंधित तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया

पटना, 05 सितम्बर 2019 ::–महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान की अध्यक्षता में राजभवन सभागार में आज एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें सितम्बर, 2019 महीने को भारत सरकार के निदेशालोक में 'पोषण माह' के रूप में आयोजित करने के लिए राज्य के नोडल विभाग –समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई तैयारियों पर आवश्यक चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री फागू चौहान ने कहा कि कुपोषण की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की तंग बस्तियों में रहनेवाले गरीब एवं अभिवंचित समुदाय के लोगों के बच्चों एवं माताओं में विशेष रूप से ज्यादा पायी जाती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में भी जागरूकता के अभाव में बच्चों का पोषण ठीक ढंग से कभी–कभी नहीं हो पाता। राज्यपाल ने कहा कि गरीब महिलाओं तथा उनके कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति विशेष सजग रहते हुए समाज–कल्याण विभाग की योजनाओं को लक्षित वर्ग तक घर–घर पहुँचाना श्रेयस्कर होगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुँचे, इसके लिए जरूरी है कि सरकारी मशीनरी एवं सामाजिक अंकेक्षण करनेवाली संस्थाएँ तत्परता एवं ईमानदारी से अनुश्रवण कार्य करें। श्री चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि रक्ताल्पता (Anemia) के कारण गर्भवती महिलाओं के बच्चे काफी कुपोषित और रोगयुक्त हो जाते हैं। माताओं से समुचित दुग्धाहार नहीं मिल पाने के कारण बच्चों में रोगनिरोधक क्षमता सही रूप में विकसित नहीं हो पाती, फलतः वे कमजोर भी जाते हैं। राज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को 'पोषण माह' के दौरान 'जागरूकता अभियान' जन–जन तक चलाये जाने का निदेश दिया। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सूचना–जनसम्पर्क एवं संबंधित अन्य विभागों के बीच आवश्यक समन्वय बनाये रखने पर भी जोर दिया ताकि जागरूकता–अभियान पूर्ण सफल हो सके।

बैठक में समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद ने राज्यपाल को बताया कि वर्तमान सितम्बर के ''पोषण माह'' के दौरान चलाये जानेवाले 'पोषण अभियान' के अन्तर्गत इसके प्रमुख पाँचों लक्ष्यों यथा– (क) गर्भधारण से लेकर 1000 दिनों तक बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा का प्रयास (ख) रक्ताल्पता (Anaemia) से मुक्ति (ग) डायरिया से मुक्ति (घ) हाथ साफ (Hand Wash) रखने के सही तौर–तरीके तथा स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था एवं (ङ) पौष्टिक आहार से जुड़े जन–जागरूकता के विशेष कार्यक्रम पूरे बिहार राज्य में संचालित होंगे।

उन्होंने बताया कि 'स्वस्थ भारत' की परिकल्पना के अनुरूप भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के तहत कुपोषणमुक्त बनाने का निर्णय लिया है तथा 0–6 वर्ष तक के बच्चों में दुबलेपन और बौनापन, अल्प पौष्टिकता एवं अन्डरवेट जन्म को

प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से घटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि 6–59 माह के बच्चों में 3 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष अनीमिया कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य सचिव श्री प्रसाद ने बताया कि कुपोषण के कारण 'अंडरवेट बच्चे' (2.5 किलो से कम वजन के) के प्रजनन में सुधार हो, इसके लिए प्रभावकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं। राज्य में आँगनबाड़ी सहायिका एवं सेविकाओं के द्वारा 'आँगनबाड़ी केन्द्रों' पर गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों की स्वास्थ्य–रक्षा के लिए समुचित प्रशिक्षण, टीकाकरण एवं उपचार आदि की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर माताओं के बेहतर स्वास्थ्य हेतु 'गोदभराई' कार्यक्रम तथा नवजात शिशुओं के लिए उनके जन्म के छः माह बाद 'अन्नप्राशन' कार्यक्रम राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित होते हैं, जिसमें बच्चों को ऊपरी आहार देना माताओं को सिखाया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों के आयोजन तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार की समुचित व्यवस्था करते हुए 'पोषण माह' को सफलतापूर्वक मनाया जायेगा।

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, आई॰सी॰डी॰एस॰ के निदेशक श्री आलोक कुमार सहित राज्यपाल सचिवालय एवं समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारीगण तथा 'यूनिसेफ' की पोषण विशेषज्ञा आदि उपस्थित थे।

.....